चोईथराम इंटरनेशनल विद्यालय, इन्दौर के तत्वावधान में आयोजित होने वाले ''मॉडल यूनाइटेड नेशन इन्दौर चैप्टर'' के अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण

1. संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चोईथराम स्कूल, इन्दौर द्वारा आयोजित ''मॉडल यूनाइटेड नेशन'' के उद्घाटन के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता है।

2. यह ''मॉडल छात्र युनाइटेड नेशन'' यूएन के कार्यकलापों एवं उनकी समितियों की महत्ता को समझने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मंचन से युवा स्कूली विद्यार्थियों को संयुक्त राष्ट्र संघ की समितियों के माध्यम से पूरे विश्व के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हित, सुरक्षा एवं मानवीय मूल्यों को समझने में सहायता होगी। यहां पर सम्मिलित कार्यसूची के विषय अत्यंत ही समसामयिक हैं जैसे ECOFIN (Economic and Financial Council) में यूरो जोन से ग्रीस का निष्कासन, DISEC (Disarmament and International Security Committee) में छोटे शस्त्रों की तस्करी एवं ड्रग तस्करी की रोकथाम पर चर्चा इत्यादि। विद्यार्थियों द्वारा अगले दो-तीन दिनों में किए जाने वाली बैठकों के माध्यम से इन विषयों पर जागरूकता बनाने में मदद करेगी। यूनाइटेड नेशन्स की कई संस्थाएं हैं जैसे WHO, UNICEF, UNDP, UNODC इत्यादि। इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य पूरे विश्व में मानव मात्र के हितों के लिए निरंतर काम करना है। इन संस्थाओं में डब्ल्यू.एच.ओ. मानव स्वास्थ्य की बेहतरी से संबंधित है। कोई संस्था बच्चों, महिलाओं एवं युवाओं के हित को प्रमुखता से लेती है तो कोई संस्था उनके सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान केंद्रित करती है।

3. देशभर के विभिन्न स्कूलों के नौंवी से बारहवीं के विद्यार्थी समसामयिक विषयों पर उपयोगी चर्चा करेंगे। इस तरह के आयोजन से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा प्राप्त करने का अर्थ केवल किताबी शिक्षा ही नहीं होती बल्कि यह वह मार्ग है जिस पर चल कर हमें भविष्य के लिए योग्य, जिम्मेवार, कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करना हैं जिनका उद्देश्य टीमवर्क के साथ भारत को दुनिया का सर्वोत्तम देश बनाना है।

4. महान चिंतक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक संत स्वामी विवेकानन्द जी ने शिक्षा के विषय में कहा था कि ''जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके। वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। इस प्रकार के आयोजन छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व को निखारने में सहायक सिद्ध होते हैं।

5. यहां इस अवसर पर विभिन्न प्रदेश से विद्यार्थी आएं हैं। उनके लिए यह एक अच्छा अवसर होगा कि वे इस सांस्कृतिक मिलन स्थली में प्रवास का आनंद उठाएं। इनकी रचनात्मकता और सृजनशीलता बहुत मायने रखती है।

6. भारत विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धान्तों का सारी दुनिया में सम्मान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं उसके संचालन के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और पद्धतियों की अवधारणा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना है। प्रथम विश्वयुद्ध में हुई धन-जन की बर्बादी एवं विभीषिका को देखते हुए सर्वप्रथम राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् सन् 1929 में हुई। भारत राष्ट्र संघ के

संस्थापक सदस्यों में से एक था। अपनी स्थापना के प्रारंभिक दिनों में यह संस्था बाल्यावस्था में थी। परंतु 1939 से 1945 तक हुए द्वितीय विश्व युद्ध ने इस संस्था को एक नया संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया और सभी देश इस बात पर राजी हुए कि वह अपने सदस्य देशों की सेनाओं को, यदि आवश्यकता पड़े तो शांति स्थापना के लिए तैनात कर सकता है। विश्व के 40 देशों ने इस संविधा पर हस्ताक्षर किए जिसमें पोलैंड भी सम्मिलित हुई। उसी समय सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्य देश बने जो संस्थापक सदस्य भी थे। वे थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है।

7. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत का संबंध ऐतिहासिक और गौरवमयी है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की। यह एक अबंधनकारी घोषणा थी, जो पूरे विश्व के लिए समान मानवाधिकारों की अवधारणा को स्थापित करती है। तब से लेकर यह पिछले 70 वर्षों से निरंतर सेवारत है एवं विश्व में शांति की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नरत है।

8. पिछले 70 वर्षों में इसमें बहुत बदलाव आए हैं और यह बदलाव आज के यूएन में परिलक्षित होना चाहिए। हम सब अवगत हैं कि इस पृथ्वी पर हर छठा व्यक्ति भारतवासी है और भारत का शांति में योगदान, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा है। अतः, समसामयिक आवश्यकताओं को स्वीकारते हुए सुरक्षा परिषद् का पुनर्गठन न केवल वांछनीय है अपितु आवश्यक भी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया के अधिकांश विकासशील देश यह मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल रहा है।

अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों की मान्यता है कि इन महाद्वीपों से कम-से-कम एक देश स्थायी सदस्य होना चाहिए ताकि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।

9. इस अवधि में जर्मनी एवं जापान विश्व के प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक शक्तियों के रूप में उभरकर सामने आये हैं। वे भी सुरक्षा परिषद् में सुधार और स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि चाहते हैं। 1946 से अब तक सुरक्षा परिषद् के 5 स्थायी सदस्य देशों द्वारा कुल 236 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है जिनमें से 103 बार रूस ने इसका उपयोग किया और इन देशों की यह अवधारणा है कि यह उन्होंने अपने भूराजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया है। अतः, सुरक्षा परिषद् में वीटो पावर के साथ नए सदस्य देशों के सम्मिलित होने से विश्व में शक्ति संतुलन के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन भी स्थापित होगा।

10. भारत के विषय में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश ने वैश्विक शांति की तरफ अभूतपूर्व योगदान किया है। भारत सात बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश है। हमारे वीर सैनिकों के मन में विश्व शांति का लक्ष्य होता है एवं वे अपनी बहादुरी एवं शौर्य से सदैव हमारा मस्तक उंचा रखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 48 मिशनों में लगभग 1 लाख 80 हजार सैनिकों को प्रतिनियुक्त किया है जिसमें से 161 वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है। इसके अतिरिक्त भारत ने अब तक लगभग 82 देशों के 800 शांति सैनिकों को विभिन्न प्रकार के शस्त्र संबंधी प्रशिक्षण दिए हैं।

11. अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि जारी मिशनों अथवा नए मिशनों के लिए 850 सैन्य दल की अतिरिक्त बटालियन के साथ-साथ महिला सैन्यकर्मियों

की बहुतायत वाली 3 अतिरिक्त सैन्य इकाई (police units) भेजने की घोषणा की है। भारत में और तैनाती स्थल में शांति सैनिकों के प्रशिक्षण के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन में तकनीकी कार्मिकों (technical personnel) को पदस्थापित किए जाने एवं हर प्रकार की सैन्य सहायता (military help) प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध (commited) हैं। वर्ष 2007 में भारत ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में पहली बार महिला सुरक्षा बल का दस्ता लाइबेरिया भेजा जो कि हमारी शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद है। यह पूरे विश्व में सुरक्षा संबंधी मामलों पर अपनी राय देती है तथा निर्णय लेती है कि उल्लंघन की परिस्थिति में किस देश पर क्या कार्यवाही की जाए। हम सभी अवगत हैं कि अफ्रीकी एवं मध्य पूर्व एशिया के देशों में संघर्ष चल रहा है और इसमें यू.एन. की भूमिका निस्संदेह महत्वपूर्ण है तथा उन्हें आगे आकर शांति एवं नागरिक हितों की सुरक्षा एवं स्थिरता लाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सीरिया में चल रहा खतरनाक हिंसक युद्ध आज पूरे विश्व के लिए चिन्ता का कारक है। इस समस्या को एकीकृत रूप में देखना आवश्यक है। भारत और यूएन की भूमिका इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम मानवता की बात करते हैं और उसे पूरे संसार के सामने प्रस्तुत करना समय की मांग है। इस मंच को हम जितना सशक्त करते हैं, उतनी मानवता के प्रति हमारा दृष्टिकोण सुरक्षित एवं संवर्धित होता है।

13. हाल ही में मेरी मुलाकात संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून जी से हुई थी, मैंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जीवन्त (vibrant) बनाने की बात की थी। भारत जैसे 125 करोड़ देशवासियों के लिए सुरक्षा परिषद् में स्थान बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था।

परन्तु, आज विश्व का ध्यान हमारी तरफ है और यही हमारी विजय है। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थीगण इस समिति के कार्यों को हूबहू समझ पाने में सफल होंगे।

14. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगले 15 वर्षों में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर एक महत्वाकांक्षी (ambitious) कार्यक्रम सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) को स्वीकृति दी। 193 देशों के यूएन की आम सभा ने एक नया फ्रेमवर्क नामतः ''Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development'' को स्वीकृत किया है जिसके अंतर्गत 17 उद्देश्यों एवं 169 लक्ष्यों को चिह्नित (identify) किया गया है जिनमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन (climate change), असमानता के विरूद्ध संघर्ष एवं गरीबी उन्मूलन (poverty alleviation) का लक्ष्य इत्यादि सम्मिलित हैं। विकास का यह नया एजेंडा विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शीर्ष वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ काफी परिश्रम एवं सलाह मशविरे के पश्चात् तैयार किया गया है।

15. 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व में विश्व योग दिवस मनाया, जो इस बात का प्रेरक है कि यह संस्था दुनिया में भारत की अच्छाई को बढ़ावा दे रही है। हम सभी जानते हैं कि योग हमारे लिए कितना आवश्यक है। यह तन, मन और आत्मा को सुव्यवस्थित करने एवं परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है। पूरे विश्व में शांति और सहिष्णुता के प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए योग आज अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। ''जियो और जीने दो'' की परम्परा को पुष्ट करता है।

16. इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा ''लोक सभा'' को भी प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें विषय होगा- संविधान की धारा 370 एवं 371 पर चर्चा और विचार-विमर्श। मैं यहां भी सार्थक चर्चा की उम्मीद करती हूं। साथ ही, उनके द्वारा आई.पी.एल. 2013 में क्रिकेट मैच के दौरान हुए स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए संबंधित विधान (Legislation) बनाए जाने से संबंधित मुद्दे को लेकर भी चर्चा की जाएगी।

17. मुझे खुशी इस बात की है कि प्रत्येक कार्यक्रम का आयोजन विद्यार्थियों द्वारा ही किया जा रहा है। मैं चाहती हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जाए ताकि संयुक्त राष्ट्रसंघ की महत्ता के बारे में देश में लोगों को अवगत कराया जा सके।

18. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय गई थी। साथ ही, इसी वर्ष जून माह में यूरोपीय पार्लियामेंट को भी देखा। वहां के लोगों में भारत के लोकतंत्र के प्रति विशेष श्रद्धा है और वे चाहते हैं कि सम्पूर्ण विश्व में समानता (Equality), सहिष्णुता (tolerance) एवं भाईचारा (fraternity) स्थापित हो। वे भी वैश्विक मंच (global stage) पर भारत के योगदान को बखूबी समझते हैं। जीवन के प्रति हमारा उदार दृष्टिकोण ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः से स्पष्ट है।

19. मैं एक बार फिर, इस कार्यक्रम के आयोजक चोईथराम अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय संगठन, चोईथराम इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों एवं अभिभावकों का अभिनंदन करती हूं।

::::::